देव नद दामोदर की दास्तान अजीब है। इसकी गोद में सभ्यता और संस्कृति का इतिहास छिपा है, मगर दामोदर घाटी परियोजना के निर्माण में एक लाख से अधिक लोगों को बेघर कर उन्हें अपनी संसकृति से दूर कर दिया गया। विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली यह नदी आज किस हाल में है, इसकी सच्चाई दर्शाती अनुपमा की यह शोधपरक रिपोर्ट।

दामोदर परियोजना सपनों से ज्यादा दर्द

दामुदर झारखण्डेक आस लागे रे,
नदी नांइ हलर इतिहास लागे रे।
जुग-जुगेक गीत गुंजे
पानी के हिलोरें
संस्कीरतिक फूल फुटल, दामुदरेक कोरें
पुरखा के मन के बिस्वास लागे रे।

शांति भारत के इस खोरठा गीत में यह बात निहित है कि दामोदर झारखंड के लिए सिर्फ नद नहीं बल्कि एक दस्तावेज है। जिसकी गोद में संस्कृति और सभ्यता का इतिहास है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 900 मिलियन क्यूबिक (90 करोड़) मीटर पानी की आवश्यकता पूर्ति दामोदार के विभिन्न स्रोतों से ही होती है। दामोदर एवं इसकी सहायक नदियां झारखंड व बिहार में एक नदी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। इस नदी घाटी व इसके इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में देश का 80 फीसदी तांबा, 85 फीसदी अबरख व क्रोमाइट, 70 फीसदी लोहा व 60 फीसदी फायरक्ले व चीनी मिट्टी उपलब्ध है।

सपही, गरगा, बराकर, कोनार, बोकोर, हाहारो, नलकारी, जमुनिया, भेड़ा, गवई, खानों व इसरी इसकी सहायक नदियां हैं। डीवीसी बनने से पूर्व इसमें 1823 से 1943 के बीच 16 बार भयंकर बाढ़ आयी। इससे जान-माल की भी क्षति हुई। इसलिए टीवीए (टेनेन्सी वैली ऑथरिटी) के चेयरमैन से दामोदर बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए संपर्क साधा गया। उन्होंने अमेरिका के विख्यात इंजीनियर डब्ल्यूएल वुडविन को जांच के लिए भेजा। उसके बाद टीवीए की नकल डीवीसी की परिकल्पना सामने आयी। जब इस परियोजना का कार्य अपने शुरूआती दौर से गुजर रहा था तभी बंगाल के सुप्रसिद्ध इंजीनियर कपिल भट्टाचार्य ने क्रिटीसाइज किया था कि 40,000 क्यूसेक पानी ले आने से भी काम नहीं चलने वाला है परंतु उनकी बातों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।

दामोदर घाटी परियोजना बनाने में करोड़ों रुपये खर्च किये गये, आज भी विभिन्न क्षेत्रों में करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, परंतु जिसकी परिकल्पना डीवीसी बनने से पूर्व की गयी थी, वह आज तक पूरी नहीं हो पायी। बंगाल को बाढ़ से बचाने के लिए तिलैया, मैथन, कोनार व पंचेत चार बांध बने। इसके जल संग्रहण के लिए अविभाजित बिहार की तकरीबन 71 हजार एकड़ उपजाऊ जमीन को ले लिया गया। एक लाख लोग बेघर हुए। 15 हजार मकान टूटे। जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा गया। बंगाल तो उबर गया परंतु जिनकी जमीनें गयीं, जिनकी जीविका छिनी वे बरबाद हो गये। तिलैया, कोनार, मैथन व पंचेत क्रवार 1953, 1955, 1957 एवं 1959 में बने। परंतु इन हाइड्रोपावर प्लांट्स से तिलैया में 4 मेगावाट, पंचेत में 40 व मैथन में 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो लक्ष्य से बेहद कम है। परियोजना बनने से पूर्व जल संग्रहण की मात्रा 28,060 लाख घन मीटर बताया गया था, जबकि यह केवल 12,030 लाख क्यूबिक मीटर ही हो पाया। यानी यह कहा जा सकता है कि परियोजना ने जितने बड़े सपने दिखाये उससे कहीं अधिक दर्द दिया है।

बंगाल में बाढ़ की विभीषिका तो रूक गयी परंतु वहां जलपोतों की यातायात प्रणाली भी बरबाद हो गयी। हुगली नदी के मुहाने पर सेडीमेंट्स (रेत व मिट्टी) जमा हो जाने के कारण कलकत्ता बंदरगाह बरबाद हो गया। कपिल भट्टाचार्य के अनुसार आगामी कुछ वर्षों में हुगली नदी के मुहाना भी 10-12 फीट ऊंचा हो जाये और कलकत्ता में जल जमाव की स्थिति बन जायेगी। इसी कारणवश अब पारादीप में नया बंदरगाह बन रहा है। फिर इतना खर्च करके इस बरबादी के मंजर को तैयार करने का आखिर मकसद क्या था यह विचारणीय है।

झारखंड सरकार धड़ाधड़ एमओयू कर रही है। जिसमें डीवीसी, सेल, टाटा, जिंदल, मित्तल, एनटीपीसी आदि शामिल हैं। स्टील के एक टन उत्पादन में 400-500 घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है। इतनी फैक्टरियों के लगाये जाने व उत्पादन के लिए जितनी बिजली की आवश्यकता होगी उसके लिए जल की उपलब्धता नहीं है और न ही यहां के थर्मल पावर प्लांट्स की क्षमता है। फिर इस एमओयू का औचित्य क्या है? यह आम आदमी की समझ से परे है। अब बात करते हैं दामोदर से निकले नहरों की। सामाजिक कार्यकर्ता त्रिभुवन एवं रम्मानी जी के अनुसार धनबाद एवं बोकारो में जितनी भी नहरें हैं उनकी पानी इतना प्रदूषित है कि उसे कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इनके इस्तेमाल से जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। जब बाढ़ आती थी तो वह अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाती थी जिससे अच्छी पैदावार होती थी। कई किस्म की मछलियां आती थीं जिससे आजीविका आसानी से चलती थी। इतना ही नहीं बाढ़ में एक विशेष प्रजाति की मछली-धनई भी आती थी। इसकी खासियत है कि यह मच्छरों के लार्वा को खाती है। इससे मलेरिया का खतरा नहीं रहता था। अब तो मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ गया है। समय था जब लोगों को मछली मारने के लिए नदी किनारे बसे लोग सिर्फ छड़ी का प्रयोग करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है और नदी का पानी प्रदूषित हो चुका है। अब तो न जल है, न जलज और न ही जलचर।

बचाने की मुहिम जारी

दामोदर बचाने की मुहिम में सरकारी मशीनरी फेल हो जाने के कारण अब यह बीड़ा स्वयंसेवी संगठनों से उठा लिया है। यह मुहिम वर्षों से बदस्तूर जारी है और जारी रहेगी। बात वर्ष 1988-1989 की है। जब महावीर जी, त्रिभुवन जी, सुरेश जी की अगुवायी में गंझूडीह के स्लरीयुक्त पानी को दामोदर में जाने से बचाने के लिए नींद हराम आंदोलन की शुरूआत हुई और इसमें सफलता उन्हें वर्ष 1991 में मिली। वर्ष 1990-91 में पर्यावरण बचाओ आंदोलन की भी शुरूआत हुई। यह आंदोलन बीटीपीएस में इएसपी लगाये जाने के लिए किया गया। साइकिल यात्रा, पदयात्रा की गयी। कारण था कि पूरे क्षेत्र में छाई का जमाव हो गया था। खेतों की फसलें बर्बाद हो गयी थी। उर्वरा क्षमता नष्ट हो गयी थी। पीटीपीएस के खिलाफ किये गये इस आंदोलन का असर इतना हुआ कि 17 जुलाई 2000 को प्लांट के उस यूनिट को बंद करना पड़ा। इसी दौरान घनश्याम जी की अगुवाई में दामोदर बचाओ अभियान के तहत दामोदर की यात्रा की गयी और नदियों के हालात पर हेमंत रणजीत ने एक पुस्तक लिखी 'जब नदी बंधी'। इस पुस्तक ने लोगों को दामोदर के प्रदूषण एवं नदियों पर बन रहे डैम की सच्चाई से अवगत किया। जनजागरूकता आने के कारण इस तीव्र आंदोलन में लोगों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी।

'दामोदर बचाओ, खुशहाली लाओ' के स्लोगन के साथ किसान विकास ट्रस्ट ने भी वर्ष 2000 से इसे बचाने का बिगूल फूंका। दामोदर को प्रदूषण मुक्त करने व डीवीसी के डैमों से किसानों को पानी मुहैया कराये जाने की मांग को लेकर जलसमाधि लेने की भी योजना बनी। परंतु जलसमाधि से पूर्व किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। दामोदर को बचाने व पानी के सवाल पर आज भी कई आंदोलन अनवरत चल रहे हैं। इन आंदोलनों में आज दामोदर बचाओ आंदोलन की भूमिका सराहनीय है। इस आंदोलन के अगुवा जमशेदपुर के विधायक सरयू राय हैं। यह आंदोलन वर्ष 2004 में शुरू हुआ। इस वर्ष अध्ययन सह जनजागरण यात्रा आयोजित की गयी।

उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरण वैज्ञानिकों का एक दल व चलंत प्रयोगशाला भी साथ-साथ थे। इसमें जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रेडरिक, पटना यूनिवर्सिटी के प्रो. आर के सिंह, जुलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया के गोपाल शर्मा, डॉ. एस के सिंह, डॉ. प्रदीप कुमार सिंह आदि के साथ अन्य लोग शामिल थे। आंदोलन ने जिन तथ्यों और आंकड़ों को अपनी स्मारिका में प्रकाशित किया वे बेहद चौंकाने वाले हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर भारती ने एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी बनाया है जिसे राज्य सरकार ने मान्यता दे दी है। यह झारखंड की पहली प्रयोगशाला है जिसमें जल, वायु एवं मिट्टी की जांच की जा सकती है। इन संस्थापकों के अलावा कई ऐसी छोटी-बड़ी संस्थाएं एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो दामोदर व स्वर्णरेखा जैसी नदियों को बचाने में जी जान से जुटे हैं। उन्हें कोई मदद भी नहीं कर रहा है पर उद्देश्य मात्र एक कि हमारा अस्तित्व, हमारा इतिहास, हमारा भविष्य, हमारा दामोदर बचा रहे।

अब पानी पीने योग्य नहीं

झारखंड की जीवनरेखा नदी दामोदर का पानी पीने वालों को सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि दामोदर का पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी भी कीमत पर पीने योग्य नहीं रह गया है। बोकारो के वाटर सप्लाई के कर्मचारी कहते हैं कि फिल्टरेशन प्लांट अभी खराब है इसलिए ब्लीचिंग पावडर और फिटकरी डालकर हम साफ पानी सप्लाई करते हैं। जारंगडीह में सप्लाई प्लांट वर्षों से खराब पड़ा है और वही पानी लोगों को पीने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। झारखंड के इकोलॉजिस्ट डॉ. एम के जमुआर के अनुसार दामोदर में आयरन जैसे भारी तत्वों की मात्रा बहुत अधिक है। इसके अलावा इसमें मैगनीज, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, लेड, आरसेनिक एवं मरकरी भी मौजूद है। आर्सेनिक की मात्रा 0.001 से 0.08 प्रति मिलीग्राम/प्रति लीटर है, मर्करी 0.002 से 0.006 मिली ग्राम/प्रति लीटर और फ्लोराइड एक से 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर है। उनका मानना है कि उद्योगों की अधिकता व खदानों ने दामोदर के पानी को पीने योग्य ही नहीं छोड़ा है। इसके प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है अंडरग्राउंड माइंस का जल बिना ट्रीटमेंट के नदी में प्रवाहित कर दिया जाना। इतना अशुद्ध व प्रदूषित जल पीने की वजह से क्षेत्र के लोगों को चर्मरोग, पीलिया, टाइफाइड, डायरिया जैसी कई बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है।

युगांतर भारती के सचिव आशीष शीतल कहते हैं कि दामोदर यात्रा के दौरान किये गये जल परीक्षण से पता चला कि दुगधा वाशरी द्वारा छोड़ा गया सल्फर युक्त स्लरी, अवांछित और विषाक्त तैलीय पदार्थ तथा कोयले के चूर्ण प्रतिबंधित मात्रा से कई गुणा अधिक हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दामोदर के जल का निरीक्षण किया था और इसे 'डी' श्रेणी का पाया था। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यह पानी न तो पीने योग्य है और न ही नहाने योग्य। लेकिन धनबाद व झरिया के 50 लाख से ऊपर की आबादी इसी जल का उपयोग करने के लिए विवश है। वाशरियों व फैक्टरियों के कचरे जिस स्थान पर दामोदर में मिलाये जा रहे हैं वहां कहीं भी पीएच नार्मल नहीं है यानी की अम्लीय है। चंद्रपुरा में यह तकरीबन 4.8 है। ऐसे विषाक्त जल से मानव जीवन के साथ-साथ जलीय जीवन भी प्रभावित हो रहा है। शोध में यह पाया गया है कि कई स्थानों पर तो इन जलीय जीवों का नामोनिशान तक नहीं है। थर्मल पावर प्लांट के अलावा रजरप्पा जैसे स्थान पर भी इनकी अनुपस्थिति चौंकाने वाली है।

वर्ल्ड हेल्थ ऑरगेनाइजेशन (डब्लूएचओ) ने अपनी प्रकाशित पुस्तक 'इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर' में जिन रासायनिक तत्वों की चर्चा की है उसे चार भागों में बांटा है। विषैले पदार्थ जिसमें मर्करी, साइनाइड, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड व सेलेनियम शामिल हैं और ये सभी के सभी दामोदर के जल में विद्यमान हैं। द्वितीय श्रेणी के वो तत्व हैं जिनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है मसलन फ्लोराइड, नाइट्रेट्स व पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ऐसे पदार्थ जो जल की वहनीयता को प्रभावित करते हैं उसे तृतीय भाग में डाला गया है। मसलन पीएच, जल का भारीपन, उसमें उपस्थित ठोस पदार्थ, तत्वों की मौजूदगी जैसे लौह, मैगनीज, जिंक, मैग्नीशियम, क्लोराइड, कैल्शियम आदि। चौथी श्रेणी में वैसे तत्व हैं जो रायासनिक संकेतक को दर्शाते हैं। घुलनशील ऑक्सीजन, क्लोराइड, नाइट्राइट्स, अमोनिया का प्रतिशत आदि दर्शाते हैं। यह विडंबना है कि दामोदर में ये सभी तत्व मौजूद हैं और इनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है। इसी कारण दामोदर के इर्द-गिर्द रहने वालों और इसके जल का उपयोग करने वालों को पेट की बीमारियां, आंत की बीमारियां, गैस्ट्रीक, पेप्टिक अल्सर से ग्रसित पाया जाता है। इसके जल के उपयोग से सांस की बीमारियां जैसे सिलिकोसिस, टीबी, एलर्जिक, ब्रांकाइटिस, न्यूयोकोनियोसिस जैसी बीमारियां आम हैं (कोयले के चूर्ण की वजह से ये होता है)। इतना ही नहीं एक्जीमा, डर्मेटोसिस, मेलिग्नेंसी जैसी चर्म की बीमारियां भी आम है। सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 70-80 फीसदी लोग इन उपर्युक्त बीमारियों में से किसी न किसी रूप से अवश्य पीड़ित हैं। कई स्थानों पर तो यह भी देखा गया है कि उनकी औसत आयु बहुत कम है और लोग बमुश्किल 50-60 की उम्र तक पहुंच पाते हैं।

उनकी मानें तो झारखंड के हजारीबाग, दुमका, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, लोहरदगा, रांची, लातेहार व लोहरदगा एवं प. बंगाल के बर्दवान, हुगली, बांकुड़ा, पुरुलिया व हावड़ा जिलों में इसका प्रभाव कमोबेश देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में नदी के किनारे पर बसे औद्योगिक संयंत्र व कारखाने तथा खदान इसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आम आदमी भी इसे प्रदूषित करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ता। परंपराओं और आस्था से जुड़े होने के कारण भी नदियों के किनारों पर अधजली व जली लाश का प्रवाहित किया जाना, पूजा-पाठ के अवशेष व घर के कचड़ों का ढेर इसमें डाला जाना इसे प्रदूषित कर रहा है। जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। इसलिए अब सचेत होने के साथ-साथ पहल की भी जरूरत है कि लोग खुद भी पहल करें और दामोदर के जल को कम से कम पीने योग्य बनाने में हर संभव प्रयास करें।

घातक बनता सीवेज वेस्ट

दामोदर में प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख कारणों में एक है–सीवेज वेस्ट। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर गोपाल शर्मा ने बोकारो में नदी के पानी का परीक्षण किया तो उसमें क्लोराइड की मात्रा 59.52 मिग्रा/ली थी। टर्बिडीटी–01–124 (एनआईआईजे), ठोस पदार्थ–125–1150 मिग्रा/ली. एवं भारीपन–32–394 मिग्रा/ली। यह मात्रा बोकारो स्टील प्लांट के डिस्चार्ज प्वाइंट के पहले ही लिये गये हैं। कोल वाशरियों से निकलने वाली गंदगी का भी यही आलम है। यहां से निकलने गंदगी 50 गुणा ज्यादा स्वीकृत परिमाण है। अधिकांशतः ये बिना ट्रीटमेंट के ही जल में बहा दिये जाते हैं। घुलित ऑक्सीजन की मात्रा यदि उचित न हो तो जलचर व जलीय पौधे विनष्ट हो जाते हैं और अधिकांश जगहों पर 6.5 मिग्रा/लीटर से कम पाया गया। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन की छह यूनिट है। इनकी क्षमता 780 मेगावाट है। पावर स्टेशन की सभी इकाइयों में मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर तथा इएसपी भी लगे हैं। परंतु आलम यह है कि ये केवल वैसे ही कोयले की राख को रोक सकते हैं, जिनमें छाई का प्रतिशत 38 फीसदी से ज्यादा न हो। लेकिन उपयुक्त कोयले में यह 55 फीसदी के आसपास है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन हो, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन या फिर ललपनिया पावर स्टेशन अमूमन यही हालात आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब थोड़ी तसल्ली है। पहले जब इएसपी नहीं लगा था तो लोगों का जीना मुहाल था। रात को यदि कोई छत पर गलती से सो जाये तो पूरे नाक में कोयला भर जाता था। इसे रोकने के लिए ऐश पौंड भी कहीं-कहीं लगाये गये हैं पर ये नाकाफी हैं। नाकाफी इसलिए की प्रदूषित जल को ये पूरी तरह साफ नहीं करते और बरसात के दिनों में तो कई बार इनका इस्तेमाल ही पूरी तरह बंद रहता है और गंदगी सीधे तौर पर नदी में भेज दी जाती है।

कोल वाशरियों का प्रदूषित जल भी इसी तरह बहाया जा रहा है। दुगधा, सिंदरी के पास छोड़े जाने वाले वाशरी के जल में सल्फरयुक्त स्लरी, विषाक्त तैलीय पदार्थ और कोयले को आसानी से देखा जा सकता है। यहां पानी का रंग कहीं भूरा, चमकीला तो कहीं एकदम से काला नजर आता है। कुछ ऐसा ही परिदृश्य नलकारी के आसपास का भी है। पतरातू बिजलीघर के पीछे भी तेलयुक्त गंदगी व राख को नदी में प्रवाहित होते देखा जा सकता है। टूटे पाइप के जोड़ों से भी राखयुक्त गंदा पानी फव्वारे के रूप में बहता दिखता है, जिसमें आसपास के खेतों को बंजर बना डाला है। अशोका प्रोजेक्ट के सामने तो पुल ने टूट कर नदी का प्रवाह ही रोक दिया है, जो कानूनन अपराध है। चंद्रपुरा थर्मल के सामने बोकारो स्टील का रंगीन पानी सीधे दामोदर में जा मिलता है। ललपनिया व बोकारो की तरह ही दुर्गापुर के प्लांट भी थर्मल प्रदूषण से दामोदर को प्रभावित कर रहे हैं। इन क्षेत्रों का पानी इतना प्रदूषित है कि इनके संपर्क में आते ही पशुओं के चमड़े जल कर गलने लगते हैं और माचिस की तीली डालते ही आग की नदी नजर आने लगती है।

प्रदूषण की मार ने आस्था को भी चोटिल व भावनाओं को दरकिनार कर दिया है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के निकट ही स्लरी के जमा हो जाने के कारण मंदिर का निचला तल पूरी तरह डूब गया है। अब मंदिर का सिर्फ ऊपरी छत से नीचे डेढ़ दो फीट भाग ही दिखायी देता है। यह शिवमंदिर आस्था का बड़ा केंद्र था पर उद्योग के आगे आस्था को स्थान कहां मिल पाता है। नदी के प्रदूषित होने के कारण आसपास के भूमिगत जल भी प्रदूषित हो गये हैं। नदी के जल में कमी के कारण 30-35 प्रतिशत नीचे तक पानी चला गया है, जो कि एक घातक संकेत है।

यदि आपने किसी को तिल-तिल मरते या घुटन भरी जिंदगी में जीते देखा होगा, तो आपको उसके दर्द का एहसास जरूर हुआ होगा। यदि यही दृश्य आपको देखना हो तो बोकारो के खेतको गांव में चलें। नदी का प्रवाह ठहर सा गया है। पूरी नदी में स्लरी जमा हो गयी है और प्रदूषण की मार साफ-साफ दिखायी देती है। खबर के अनुसार जब जांच टीम केदला वाशरी गयी थी तो नदी के किनारों पर जमे कोयले के चूर्ण को छुपाने के लिए एक किलोमीटर दूर तक बालू डलवाया गया था। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर नदी में पूरी तरह कालिमा छायी थी। इस मसले पर तत्कालीन सीसीएल के डायरेक्टर आर के साहा ने रिपोर्ट भी मंगवाकर देखा था। मूरी के आसपास तो नदी में आप जिंदा मछली डालेंगे तो वह कुछ देर बाद नदी की तलहटी पर मरी हुई तैरती नजर आयेगी। वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव सुधीर प्रसाद के अनुसार एक यूनिट बिजली के उत्पादन से चार किलो फ्लाई ऐश का उत्पादन होता है। झारखंड में अभी 20 लाख टन फ्लाई ऐश है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है सिवाय प्रदूषण बढ़ाने के। सरकार को फ्लाई ऐश ब्रीक बनाकर बेचना चाहिए ताकि पर्यावरण की कुछ तो रक्षा हो सके।

दामोदर को प्रदूषित करने का सिलसिला यदि अब भी नहीं थमता, तो वह दिन दूर नहीं है जब हम आने वाली पीढ़ियों को उनकी पुस्तकों में नदी का इतिहास बतायेंगे और यह पढ़ायेंगे दामोदर एक नद था। जिसने कृषि व औद्योगिक विकास के नाम पर अपनी कब्र स्वयं ही खोद ली।

(सीएसई मीडिया फेलोशिप के तहत शोध अध्ययन रिपोर्ट)

तापघरों से फ्लाई ऐश की उत्पत्ति

विद्युत तापघरों के नाम	कुल राख प्रतिदिन
1. बोकारो विद्युत तापघर (इकाई अ)	906 टन
2. बोकारो विद्युत तापघर (इकाई ब)	1200 टन
3. चंद्रपुरा विद्युत तापघर	4000 टन
4. पतरातु विद्युत तापघर	2620 टन

स्रोत: केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद